



HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

RNI No. : MAHHIN/2011/24374

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

वर्ष : १०

अंक : ५१

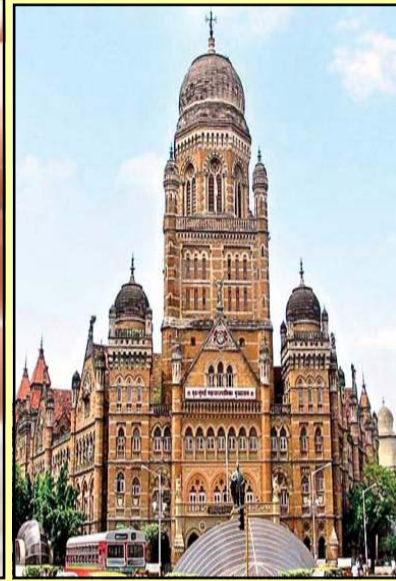
मुंबई, शुक्रवार, २० अगस्त से २६ अगस्त २०२१

पृष्ठ : ४

मुल्य : ₹. २/-

कोरोना से मौत को मात, डेथ रेट पर काबू पाने का बीएमसी का प्रयास सफल

मुंबई : मुंबई में कोरोना मरीजों की घटती संख्या एवं बेहतर होते रिकवरी रेट से डेथ रेट में भारी गिरावट आई है। मुंबई में ओवरऑल डेथ रेट २ प्रतिशत के आसपास है, लेकिन अगस्त में इसमें काफी गिरावट आई है। १ अगस्त से १७ अगस्त के बीच मुंबई में कोरोना के ४६३६ नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से ९९ लोगों की मौत हुई। इसमें १ अगस्त को सर्वाधिक १० लोगों की मौत भी शामिल है। अगस्त के १७ दिनों में कोरोना से मरने वालों की दर ०.०००२१ प्रतिशत रही। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता



है कि बीएमसी ने कोरोना से होने वाली डेथ रेट पर किस तरह से रोक लगाई है।

बीएमसी की एग्जेक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह ने कहा कि बीएमसी इस पर लगातार काम कर रही है। लोगों को तुरंत इलाज और आवश्यकता के अनुसार दवा की व्यवस्था से डेथ रेट पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एक साथ हमने ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया। (पृष्ठ ३ पर)

मीठी नदी के लौटेंगे अच्छे दिन

सीवरेज का पानी रोकने बीएमसी बनाएगी 6 किमी लंबी टनल, 500 करोड़ होंगे खर्च

मुंबई : लगभग नाले में तब्दील हो चुकी मुंबई के बीचो-बीच बहने वाली मीठी नदी के भी अच्छे दिन लौटेंगे। मीठी नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बीएमसी ने सीवरेज के बहाव को रोकने का फैसला किया है। कुर्ला में मीठी नदी में गिरनेवाले दो नालों के गंदे पानी को ६ किमी अंडर ग्राउंड टनल बनाकर धारावी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने बताया कि ५०० करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है।



६.५ किमी लंबी होगी। इसके निर्माण में कुल ५०० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अन्य करों सहित कुल लागत ६०४ करोड़ रुपये तक जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार को टनल का काम ४८ महीने (बरसात छोड़ कर) पूरा करना होगा।

बता दें कि वर्ष २००५ में आई बाढ़ में मीठी नदी में उफान के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। उसके बाद गठित कमिटी ने मीठी नदी की साफ-सफाई, गहराई एवं चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा दीवार बनाने का सुझाव दिया था। उसी के तहत यह सब कार्य हो रहे हैं।

जाधव ने कहा कि मीठी नदी को बेहतर बनाने के लिए उसके पानी की सफाई, सुरक्षा दीवार का निर्माण, सौंदर्यीकरण, साइकल ट्रैक जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मीठी नदी की सफाई के लिए कुछ स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी टनल बनाई जाएगी, जो वर्ष २०५१ तक प्रतिदिन अनुमानित १६८ मिलियन लीटर सीवरेज के पानी को धारावी ट्रीटमेंट प्लांट में भेज सके। यह टनल २.६ मीटर व्यास और

केंद्र ने ओबीसी समाज को फंसाया : शरद पवार

मुंबई : ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने ओबीसी समाज को फंसाया है, ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया। आरक्षण के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन विधेयक रखने का मतलब आरक्षण का रास्ता साफ हो गया, ऐसा कई लोगों को लग रहा है लेकिन यह गलतफहमी है, असल में ओबीसी समाज को शुद्ध रूप से फंसाने का काम केंद्र ने किया है। पहले हाथ बांधने का और फिर



उन्हें भोजन के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करने जैसा है, ऐसा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र (पृष्ठ ३ पर)

Let's Join Media to Fight Against Corruption & Crime
Low Cost Franchisee Opportunity



CRIME
THE MOST WANTED T.V. NEWS



HAR-PAL T.V. NEWS



Crime Investigation News

Contact : 7498535286

Website : www.crimeinvestigationharpal.com / Email : harpaltimes.press@gmail.com

Mumbai Office : 2-B, Nityanand Nagar, KC Marg, Opp. Reclamation Bus Depot, Behind ONGC Colony,

Next to Lilavati Hospital, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

Samhitha Residency, B1. Rkm Layout, Margondahalli, Bangalore.



॥ निर्भीक प्रकाशिता लोकतंत्र की आवश्यकता ॥

संपादकीय



शर्मसार न हो इंसानियत

अफगानिस्तान का फिर बर्बरता के शिकंजे में चले जाना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। कथित इस्लामी सत्ता की स्थापना के लिए तालिबान जो कर रहा है, उसकी दुनिया में शायद ही किसी कोने में प्रशंसा होगी। दुनिया स्तब्ध है और भारत जैसे देश तो कुछ ज्यादा ही आहत हैं। हम उस इतिहास में जाकर कतई भावुक न हों कि अफगानिस्तान कभी भारत वर्ष का हिस्सा था, जहां सनातन धर्म और बौद्धों का वर्चस्व था, हमें अभी अपने उस तन-मन-धन के निवेश पर गौर करना चाहिए, जो हमने विगत कम से कम बीस वर्षों में वहां किया। एक उदारवादी ताकत के रूप में न जाने कितनी विकास परियोजनाओं में भारत की वहां हिस्सेदारी रही। लगभग तीन हजार भारतीय अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगे थे। एक अनुमान के अनुसार, भारत ने वहां २.३ अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम चला रखे हैं, अब उनका क्या होगा? भारत और भारतीयों द्वारा वहां मानवीय सहायता, शिक्षा, विकास, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का क्या होगा? आम अफगानियों के मन में भारत के प्रति अच्छे भाव हैं, लेकिन तालिबान का रुख तलख ही रहा है।

बहरहाल, भारतीय ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लोग भी अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और तालिबान में इतनी सभ्यता भी नहीं कि वह लोगों को रोकने के लिए कोई अपील करे। संयुक्त अरब अमीरात भी मजहबी आधार वाला देश है, लेकिन उसने कैसे दुनिया भर के अच्छे और योग्य लोगों को जुटाकर अपने यहां आदर्श समाज जुटा रखा है, लेकिन अफगानिस्तान में जो इस्लामी खलीफा शासन स्थापित होने वाला है, उसमें इतनी सभ्यता भी नहीं है कि उन लोगों को रुकने के लिए कहे, जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में दिन-रात एक किए हुए थे। विगत दशकों में तालिबान ने एकाधिक आतंकी हमले सीधे भारतीय दूतावास पर किए हैं और अपनी मंशा वह साफ कर चुका है। कंधार विमान अपहरण के समय तालिबान की भूमिका भारत देख चुका है। क्या दुनिया के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा? क्या ये पैसे लेकर सभ्य देशों को परेशान करने और निशाना बनाने का ही काम करेंगे? जो देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालिबान की पीठ पीछे खड़े हैं, उनकी भी मानवीय जिम्मेदारी बनती है।

अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की कोशिश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के बचाव के लिए विशेष बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी भारत के पास परिषद की अध्यक्षता है, क्या उसे नए सिरे से पहल नहीं करनी चाहिए? तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है और अभी सभी का ध्यान अपने-अपने नागरिकों को बचाने पर है, लेकिन आने वाले दिनों में व्यवस्थित ढंग से सोचना होगा कि ताकत और पैसे के भूखे आतंकियों के खिलाफ क्या किया जाए? हां, यह सही है कि तालिबान में भी सभी आतंकी नहीं होंगे, कुछ अपेक्षाकृत सभ्य भी होंगे, जो अपने देश की बदनामी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण न रुके। अफगानी युवाओं को बंदूकों के सहारे ही जिदगी न काटनी पड़े। महिलाओं की तौहीन न हो। अफगानिस्तान दुनिया में नफरत और हिंसा बढ़ाने की वजह न बने। कुल मिलाकर, उदारता और समझ की खिड़की खुली रहनी चाहिए, ताकि इंसानियत शर्मसार न हो।

अल्लाह का महीना है मुहर्रम

इस्लामी यानी हिजरी सन् का पहला महीना मुहर्रम है। हिजरी सन् का आगाज इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के चार पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है। साथ ही इस मास में रोजा रखने की खास अहमियत बयान की है।

मुख्तलिफ हदीसों, यानी हजरत मुहम्मद (सल्ल.) के कौल (कथन) व अमल (कर्म) से मुहर्रम की पवित्रता व इसकी अहमियत का पता चलता है। ऐसे ही हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने एक बार मुहर्रम का जिक्र करते हुए इसे अल्लाह का महीना कहा। इसे जिन चार पवित्र महीनों में रखा गया है, उनमें से दो महीने मुहर्रम से पहले आते हैं। यह दो मास हैं जीकादा व जिलहिज्जा।

एक हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा कि रमजान के अलावा सबसे उत्तम रोजे वे हैं, जो अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम में रखे जाते हैं। यह कहते समय नबी-ए-करीम हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने एक बात और जोड़ी कि जिस तरह अनिवार्य नमाजों के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद की है, उसी तरह रमजान के रोजों के बाद सबसे उत्तम रोजे मुहर्रम के हैं। इस्लामी यानी हिजरी सन् का पहला महीना मुहर्रम है। हिजरी सन् का आगाज इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के चार पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने इस मास को अल्लाह का महीना कहा है।

इतिफाक की बात है कि आज मुहर्रम का यह पहलू आमजन की नजरों से ओझल है, और इस माह में अल्लाह की इबादत करनी चाहीये जबकि पैगंबरे-इस्लाम (सल्ल.) ने इस माह में खूब रोजे रखे और अपने साथियों का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया। इस बारे में कई प्रामाणिक हदीसों मौजूद हैं।

मुहर्रम की ९ तारीख को जाने वाली इबादतों का भी बड़ा सवाब बताया गया है। हजरत मुहम्मद (सल्ल.) के साथी इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा कि जिसने मुहर्रम की ९ तारीख का रोजा रखा, उसके दो साल के गुनाह माफ हो जाते हैं तथा मुहर्रम के

एक रोजे का सवाब (फल) ३० रोजों के बराबर मिलता है। गोया यह कि मुहर्रम के महीने में खूब रोजे रखे जाने चाहिए। यह रोजे अनिवार्य यानी जरूरी नहीं हैं, लेकिन मुहर्रम के रोजों का बहुत सवाब है।

अलबत्ता यह जरूर कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह के नबी हजरत नूह (अ.) की किशती को किनारा मिला था। इसके साथ ही आशूरे के दिन



यानी १० मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी, जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक स्थित कर्बला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्योछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। इस घटना में हजरत मुहम्मद (सल्ल.) के नवासे (नाती) हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। कर्बला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय है। बुजुर्ग कहते हैं कि इसे याद करते हुए भी हमें हजरत मुहम्मद (सल्ल.) का तरीका अपनाना चाहिए। जबकि आज आमजन को दीन की जानकारी न के बराबर है। अल्लाह के रसूल वाले तरीकोंसे लोग वाकिफ नहीं हैं। ऐसे में जरूरत है हजरत मुहम्मद (सल्ल.) की बताई बातों पर गौर करने और उन पर सही ढंग से अमल करने की जरूरत है।

करबला की जंग

-करबला, इराक की राजधानी बगदाद से १०० किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व में एक छोटा-सा कस्बा।

-१० अक्टूबर ६८० (१० मुहर्रम ६१ हिजरी) को समाप्त हुई।

-इसमें एक तरफ ७२ (शिया मत के अनुसार १२३ यानी ७२ मर्द-औरतें और ५१ बच्चे शामिल थे) और दूसरी तरफ ४०,००० की सेना थी।

-हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्ने अली थे। उधर यजीदी फौज की कमान उमर इब्ने सअद के हाथों में थी।

-हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब

-हजरत अली और पैगंबर हजरत मुहम्मद की बेटी फातिमा (रजि.) के पुत्र।

-जन्म : ८ जनवरी ६२६ ईस्वी (मदीना, सऊदी अरब) ३ शाबान ४ हिजरी

-शहादत : १० अक्टूबर ६८० ई. (करबला, इराक) १० मुहर्रम ६१ हिजरी।

मुहर्रम और आशुरा

मुहर्रम महीने के १० वे दिन को आशुरा कहते हैं। आशुरा के दिन हजरत रसूल के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके बेटे घरवाले और उनके साथियों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया।

इस्लाम एक ऐसा धर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति सही नियमों से इस धर्म का पालन करें और

मोहम्मद पैगम्बर की बातों को अपनी निजी जिन्दगी में उतार लें चाहे वो उन नियमों का अपनाने में थोड़ा बहुत आलसी किस्म का है। लेकिन थोड़ा सा भी अमल कर लें तो उसकी जिन्दगी में अल्लाह की तरफ से कोई शिकायत नहीं रहती क्योंकि अल्लाह ये बात नहीं कहता कि तुम इस्लाम बनो ओर ना ही ये बात कहते हैं कि तूम मेरी इस सभा में रोज शामिल हो लेकिन उन्होनें तो एक मुस्लमान से तो बस थोड़ा सा ही वक्त मांगा है। वो भी जूममें की दोपहर का। क्या हो जाता है की अगर कोई मुसलमान सप्ताह के एक दिन जूममें के दिन में दोपहर को आराम न करें तो वो आदमी मर नहीं जाता और कोई कठिन कार्य के लिए भी नहीं कहा है। ना कि तूम मेरे लिए कोई ऐसा काम करो जिससे आपको काफी मेहनत भी करनी पड़े लेकिन हां मस्जिद में जाकर दोपहर केवल ३० मिनट ही नमाज पढले तों वो और उसके अन्दर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी तो नहीं होता। मेरी मानों तो दोस्तों इस्लाम को किसी भी प्रकार का खतरा है तो वो एक खुद किसी मूसलमान से है जो दिन में नमाज नहीं पढता अगर इस कौम को कोई खतरा है तो वो है इस्लाम व पैगम्बर में बनाये नियमों का पालन न करने वालो लोगों से ही है।

क्यों कि कहते हैं कि अल्लाह ने रोटी की व्यवस्था तो हमारे जन्म लेने से पहले ही कर दी फिर भी हम इस दूनियां में आकर रोटी के लिए ही भागतें फिरतें ही और पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते।

संपत्ति के लिए हत्या किये... (पृष्ठ ४ का शेष)

पाल पर लुटेरों ने धन की लूटपाट के मकसद से हमला किया हो, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तब उसे हमलावर का कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारी ने कहा, "पुलिस तब स्तब्ध रह गयी जब रविवार को होश आने के बाद पाल ने लिखकर बताया कि उसने खुद ही अपना गला काट लिया और पुलिसकर्मीयों से ऑटोरिक्शे में रखे नोट लाने को कहा।" अधिकारी के अनुसार, पुलिस को नोट के जरिए पता चला कि मुंबई में नकद समेत पाल की कुछ संपत्ति है लेकिन वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रह रहा था क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह संपत्ति पर दावे के लिए उसकी जान ले लेगा।

मध्य रेल ने भंगार से कमाए... (पृष्ठ ४ का शेष)

वर्ष २०२१-२२ के लिए ८४०० करोड़ स्क्रैप बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि स्क्रैप की बिक्री से न केवल राजस्व अर्जित करने में मदद मिल रही है, बल्कि परिसर के बेहतर रख-रखाव में भी मदद मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य रेल विभिन्न स्थानों पर चिन्हित सभी स्क्रैप सामग्री को बेचने के लिए मिशन मोड में काम करेगा।

केंद्र ने ओबीसी समाज... (पृष्ठ १ का शेष)

सरकार पर लगाया। मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में शरद पवार ने कहा कि संविधान संशोधन करके राज्य को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया। इसके कारण आरक्षण के लिए सरकार ने कदम उठाया है, ऐसा लोगों को गलतफहमी हुई है; यह ओबीसी समाज को शुद्ध रूप से फंसाने की चाल है। १९९२ में ९ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ऐसा खंडपीठ ने कहा था। बाद में केंद्र ने १० फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करके प्रावधान किया। अब केंद्र ने ओबीसी की सूची संकलित करने का अधिकार राज्य को देकर आरक्षण राज्य तय कर सकते हैं, ऐसी भूमिका केंद्र ने ली है। इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इस संविधान संशोधन से ओबीसी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा पवार ने कहा।

कोरोना से मौत को... (पृष्ठ १ का शेष)

जिन्हें गंभीर बीमारी थी, उनका ज्यादा ध्यान रखा गया। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज दी गई, उसी का नतीजा है कि हम कोरोना से डेथ को कंट्रोल करने में सफल रहे। जो लोग होम क्वारंटीन थे या हैं, उन पर वॉर्ड वॉर रूम से नजर रखी जा रही है। फोन के जरिए उनसे अपडेट लिया जा रहा है। यदि किसी की तबियत बिगड़ती है, तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। इससे मरीज की स्थिति क्रिटिकल नहीं होने पा रही है। अब तो हॉस्पिटल व जंबो कोविड सेंटर में भी खाली बेड्स की संख्या अधिक है।

अप्रैल, २०२० के बाद १७ अगस्त, २०२१ को कोरोना से सिर्फ २ मरीजों की मौत हुई। पूरे अगस्त में प्रतिदिन ४ से लेकर ९ लोगों की मौत प्रतिदिन कोरोना से हुई है, वहीं कोरोना मरीजों की बात करें, तो इस दौरान कई दिन २०० से कम मरीज मिले हैं। ज्यादातर दिन २०० से ३०० के बीच मरीज मिले हैं।

मुंबई में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट (०.०५ प्रतिशत) ४ वॉर्डों में है, जिनमें गोवंडी, परेल, कोलाबा व माटुंगा शामिल हैं। डबलिंग रेट की बात करें, तो मुंबई में यह २०५७ दिन तक पहुंच गया है। बांद्रा पूर्व में ३६८० दिन, कालबादेवी में ३३१९ दिन, मालाड में ३२२८ दिन, दादर में २९७७ दिन, मुलुंड में २९११ दिन एवं बोरिवली में २६२९ है। सबसे कम डबलिंग रेट गोवंडी में १२८५ दिन, परेल में १२८९ दिन एवं कोलाबा में १३०१ दिन है।

कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अंधेरी वेस्ट में हैं। यहां अब तक ५५१६० मरीज मिले हैं, जिनमें से ५४००० लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि ७४४ लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल, यहां कोविड के १८२ ऐक्टिव मरीज अब भी हैं। अंधेरी पूर्व में अब तक मुंबई में सबसे ज्यादा १२५७ मौतें कोरोना की वजह से दर्ज की गई हैं। यहां अब तक ४६३०५ मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से ४४६६१ लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि १७४ मरीजों का अब भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

५ फर्जी डॉक्टरों पर चला कानून का डंडा

मुंबई : चिकित्सक को लोग धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं लेकिन आज चिकित्सक का पेशा कमाई का रास्ता बन गया है। इसी वजह से आज चिकित्सा के पेशे में बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टरों की घुसपैट हो गई। ये डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल किए बगैर ही मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। ५ ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों पर कल कानून का डंडा चला। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट ६ के अधिकारियों की सतर्कता के कारण फर्जी डॉक्टरों के ठगी की दूकान बंद हो गई है। बता दें कि मुंबई की झोपड़पट्टी बहुल गोवंडी इलाके में बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाए जाने की सूचना क्राइम ब्रांच यूनिट-६ के पीआई हनुमंतराव ननावरे व उनके सहयोगी एपीआई नीतिन



सावंत को मिली थी। डीसीपी दत्ता नलावडे के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र सालुंखे के नेतृत्व में यूनिट-६ की टीम ने मामले की जांच की। जांच में पता चला कि शिवाजी नगर पुलिस थाने अंतर्गत बैंगन वाड़ी इलाके में ५ डॉक्टर अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र मेडिकल कौंसिल में उनका पंजीकरण नहीं हुआ है और उनके पास डॉक्टरों की डिग्री भी नहीं है। यूनिट ६ की टीम ने मनपा एम-पूर्व विभाग की सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रिया कोली व उनके सहयोगियों के साथ फर्जी डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में डॉक्टरों के क्लिनिक से दवाइयां, इंजेक्शन एवं चिकित्सा से संबंधित उपकरण जप्त किए गए।



सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन

आइए कोविड मुक्ति की शपथ लें!



७५ 

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!



श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
मा. मुख्यमंत्री

श्री. अजित पवार
मा. उप मुख्यमंत्री

श्री. बाळासाहेब थोरात
मा. मंत्री, राजस्व

सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार



मुंबई : कोरोना महामारी के कारण ट्रेनों और चेक नाकों पर जांच सख्त होने से यूपी-बिहार के शस्त्र निर्माताओं पर अंकुश लगा है, क्योंकि वे प्रतिबंधित शस्त्र दूसरे राज्यों में नहीं भेज पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अवैध शस्त्र निर्माता इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। वे सब्जी के ट्रकों में पिस्तौल और दूसरे प्रतिबंधित शस्त्र महाराष्ट्र और आसपास

के दूसरे राज्यों में आसानी से पहुंचा रहे हैं और मौत का ये सामान महज ३० हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं। इसका खुलासा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ७ ने किया है।

बता दें कि यूनिट- ७ की टीम को अवैध शस्त्रों की विक्री के सिलसिले में तस्करों के आने की सूचना मिली थी। डीसीपी दत्ता नलावडे के मार्गदर्शन

एमपी बनी अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री

सब्जी के ट्रक में हथियार सप्लायर, ८ पिस्तौल के साथ २ धराए

तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष श्रीधनकर के नेतृत्व में एपीआई आनंद बागडे, अमोघसिद्धि ओलेकर, पीएसआई माधवानंद धोत्रे, नीलेश चव्हाण आदि की टीम ने विक्रोली-पूर्व स्थित सर्विस रोड के पास जाल बिछाकर दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। उनकी तलाशी में उन्नत किस्म के ८ देसी पिस्तौल और ७ जिंदा कारतूस जप्त किए हैं। जांच में पता चला है कि २१ वर्षीय आरोपियों में से एक का पिता मध्यप्रदेश में हुई सबसे बड़ी डकैती और हत्या मामले में शामिल था।

अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी थी। कुछ समय पहले वह जेल से पैरोल पर छूटा था। उसी दौरान उसने अवैध शस्त्र बेचना शुरू किया था। उसने अपने साथ अपने बेटे को भी इस गैरकानूनी कार्य में लगा लिया।

गौरतलब हो कि यूनिट ७ की टीम ने इसी साल जून महीने में एमपी के खरगोन जिले से लाए गए १० देसी पिस्तौलों और १२ मैगजीन के

साथ एक २१ वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया था। यूनिट ७ की टीम अब दोनों मामलों के बीच के लिंक की जांच कर रही है। साथ ही मुंबई में शस्त्र मांगने वाले लोग और उनके मकसद की जांच पुलिस कर रही है। ऐसी जानकारी डीसीपी दत्ता नलावडे ने दी। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत ने २३ अगस्त तक पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

सिलिंडर हुआ २५ रुपए महंगा; सालभर में बढ़े २७५ रुपए दाम

मुंबई : कोरोना काल में तंगी से जूझ रहे आम आदमी की रसोई में वैसे ही स्वाद फीका था लेकिन अब केंद्र सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की नीति के चलते आम लोगों के घरों की रसोई में महंगाई का 'तड़का' लगा है। सामान्य परिवार को एक बार फिर झटका देते हुए पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोत्तरी कर दी है। इन कंपनियों ने जनता की मौजूदा हालत को नजरअंदाज करते हुए नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलिंडर की कीमत २५ रुपए बढ़ा दी है।

मुंबई और दिल्ली में १४.२ किलोवाले एलपीजी सिलिंडर की कीमत अब ८५९.५ रुपए हो गई है जबकि इससे पहले ये ८३४.५० रुपए का मिल रहा था। इसके पहले १ जुलाई को सिलिंडर के दाम २५.५० रुपए बढ़ाए गए थे। आंकड़ों के अनुसार



पिछले एक वर्ष में कई बार पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलिंडर के दाम बढ़ाए हैं। एक वर्ष में सिलिंडर की कीमतों में २७५ रुपए की वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गैस सिलिंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। सिलिंडर की कीमतों में मानों पंख लग गया है। इस वर्ष जनवरी से देखें तो सिलिंडर के दाम १६५.५० रुपए तक बढ़ चुके हैं जबकि एक साल में लगभग २७५

रुपए की वृद्धि हुई है। साल २०२१ की शुरुआत यानी जनवरी में मुंबई और दिल्ली में एलपीजी सिलिंडर का दाम ६९४ रुपए था, जिसे फरवरी में बढ़ाकर ७१९ रुपए किया गया। फिर १५ फरवरी को इसमें ७६९ रुपए की वृद्धि की गई। इसके बाद २५ फरवरी को सिलिंडर के दाम ७९४ रुपए और मार्च में फिर बढ़ाकर ८१९ रुपए कर दिया गया। अप्रैल की शुरुआत में हुई १० रुपए की कटौती के बाद घरेलू रसोई गैस के दाम दिल्ली में ८०९ रुपए हो गए थे।

संपत्ति के लिए हत्या किये जाने के डर से ऑटोरिक्षा चालक ने अपना गला काट लिया

मुंबई : मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र मुलुंद में ४० वर्षीय एक ऑटोरिक्षा चालक ने इस भय से अपना गला काट लिया कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है और महानगर में संपत्ति के लिए उसकी जान ले लेगा। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सायन अस्पताल में लालजी पाल नामक इस चालक का इलाज चल रहा है। विचित्र बात है कि पाल अपने ऑटोरिक्षा के चालक सीट के नीचे धारदार हथियार और एक नोट रखता है जिसमें उसने अपने डर का उल्लेख कर रखा है। उसी

जगह पर उसने नामित व्यक्ति का भी नाम भी लिख रखा है। अधिकारी ने बताया कि गला कटा होने से बोलने में असमर्थ पाल लिखकर पुलिस के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। उनके अनुसार शुक्रवार को मुलुंद में पी के रोड पर पाल ने तडक्रे अपना गला काट लिया एवं जब वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उसे खून से लथपथ देखा, तब उसने पुलिस को उसकी सूचना दी।

पुलिस ने शुरू में यह मानकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भादंस की धारा ३०७ (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया कि (पृष्ठ ३ पर)

मध्य रेल ने भंगार से कमाए ३९१.४३ करोड़

मुंबई : मध्य रेल ने वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान ३५० करोड़ रुपये के स्क्रैप बिक्री लक्ष्य को पार कर ३९१.४३ करोड़ रुपये का स्क्रैप बेचा है, जो पिछले १५ वर्षों में सबसे अधिक है। रेलवे ने 'जीरो स्क्रैप मिशन' शुरू किया था। इस स्क्रैप सामग्री में स्क्रैप रेल, पर्मानेंट वे सामग्री, खराब कोच, वैगन और लोकोमोटिव आदि शामिल हैं। इनको बेचकर एक रेवेन्यू भी जनरेट करने का लक्ष्य होता है। इस स्क्रैप को ऑनलाइन प्रक्रिया या अन्य पारदर्शी तरीका अपनाकर नीलाम किया जाता है। (पृष्ठ ३ पर)

